

Delhi to Become National Hub of Cooperatives State government prepares, cooperative stores to open from new year

सहकारिता का नेशनल हब बनेगी दिल्ली प्रदेश सरकार ने की तैयारी, नए साल से खुलेंगे को-ऑपरेटिव स्टोर

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी को सहकारिता का नेशनल हब बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने जा रही है। सहकारिता, समाज कल्याण, एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण एवं चुनाव मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार सहकारिता से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने, उनकी मार्केटिंग में सहायता करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

नाबार्ड के स्टेट एम्पोरिया काम्प्लेक्स में आयोजित सहकार हाट के शुभारम्भ अवसर पर मंत्री ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है। ऐसे में दिल्ली को सहकारिता उत्पादों की मार्केटिंग का केंद्र बनाकर देशभर के किसानों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को सीधा लाभ पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि

सहकारिता से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने, मार्केटिंग में करेंगे सहायता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि का संकल्प आज एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुका है। वर्ष 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों की अहम भूमिका होगी। जब किसान, कारीगर और छोटे उद्यमी मजबूत होंगे, तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि दिल्ली की हाउसिंग सोसायटीज में आधुनिक को-ऑपरेटिव स्टोर खोले जाने की योजना है। नए साल से राजधानी में कई सहकारिता स्टोर शुरू किए जाएंगे, जहां हैंडलूम, हस्तशिल्प, कृषि और ग्रामीण उत्पादों को उचित बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करेगी, जिसके

दिल्ली के एकमात्र महिला हाट का होगा कायाकल्प : सत्या शर्मा

नई दिल्ली। आसफअली रोड स्थित एमसीडी के एकमात्र महिला हाट का जल्द ही कायाकल्प किया जाएगा। वर्षों से बदहाल पड़े इस महिला हाट की स्थिति पर संज्ञान लेते हुए स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने इसके सुधार और पुनर्विकास को लेकर भावी योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष रेखा रानी की उपस्थिति में महिला हाट का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि महिला हाट के पुनर्जीवन के लिए एक विस्तृत भावी योजना तैयार की जाएगी, जिसके तहत समुदाय सेवा विभाग को पुनर्विकास का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वित्तीय व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों को दोबारा स्थापित करने की ठोस रूपरेखा शामिल होगी। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जब तक महिला हाट में पहले की तरह स्टॉलों की स्थापना पुनः शुरू नहीं हो जाती, तब तक परिसर के रखरखाव में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो

माध्यम से सहकारिता से जुड़े लोग पंजीकरण कर अपने उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकेंगे। इससे छोटे उद्यमियों को नए अवसर मिलेंगे और सहकारिता नेटवर्क का विस्तार होगा। मंत्री ने बताया कि दिल्ली में 2000 से अधिक सहकारिता सोसायटीज हैं, लेकिन

पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान यह क्षेत्र उपेक्षित रहा। अब सहकारिता संस्थाओं, बैंकों और क्रेडिट सोसायटीज को मजबूत करने के लिए आवश्यक कानूनी संशोधनों और संरचनात्मक सुधारों पर नाबार्ड के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है।

Affordable Home Loans Available to Middle and Lower Income Groups Through Cooperatives

Government to Expand DCHFC, Affordable Home Loans Easily Available in Delhi

सहकारिता के जरिये मध्यम, निम्न आय वर्ग को मिलेगा सस्ता होम लोन

सरकार डीसीएचएफसी का करेगी विस्तार, दिल्ली में आसानी से मिलेगा सस्ता होम लोन

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली में सहकारिता के जरिये मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ते होम लोन मिलेंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड (डीसीएचएफसी) का विस्तार करेगी। इसके तहत अगले माह रोहिणी में डीसीएचएफसी का नया कार्यालय खोला जाएगा।

दिल्ली सरकार के सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने

अगले माह रोहिणी में
खुलेगा डीसीएचएफसी का
नया कार्यालय

डीसीएचएफसी के विस्तार को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में निगम के काम, ऋण वितरण, वसूली की स्थिति, वित्तीय मजबूती और भविष्य की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि डीसीएचएफसी का लाभ अधिक से

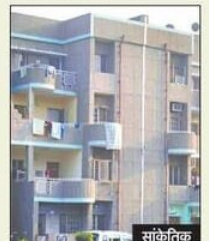
अधिक दिल्लीवासियों तक पहुंचे और इसके लिए नई शाखाएं शुरू की जाएं। अधिकारियों ने बताया कि रोहिणी में खुलने वाला कार्यालय सीरी फोर्ट के बाद दिल्ली में डीसीएचएफसी का दूसरा कार्यालय होगा।

इससे उत्तर-पश्चिम दिल्ली और आसपास के इलाकों के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही अन्य उपयुक्त स्थानों पर भी कार्यालय खोलने की व्यावहारिक योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

डीसीएचएफसी की योजनाओं का होगा प्रचार : मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान सहकारी क्षेत्र की अनदेखी हुई, लेकिन अब सरकार की प्राथमिकता है कि मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग और सहकारी आवास समितियों से जुड़े लोगों को कम ब्याज दर पर आसान होम लोन मिले। उन्होंने जन जागरूकता और प्रचार प्रसार मजबूत करने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा, ताकि लोग डीसीएचएफसी की योजनाओं से परिचित हो सकें।

लोन की प्रक्रिया और स्वीकृति होगी सरल

डीसीएचएफसी को तकनीकी रूप से मजबूत किया जाएगा, जिससे ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया सरल, समयबद्ध और पूरी तरह पारदर्शी होगी। डीसीएचएफसी के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में सहकारी समूह आवास सोसाइटी में फ्लैट या मकान की खरीद, डीडीए से फ्लैट या मकान के आवंटन, मकान के नवीनीकरण और फ्रीहोल्ड संपत्ति की खरीद के लिए ऋण दिया जाता है। वहीं, सोसाइटीज को डीडीए से भूमि खरीदने, परियोजना पूरी करने के लिए ब्रिज लोन, लिफ्ट बदलने, बाहरी विकास कार्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर सिस्टम लगाने जैसे कार्यों के लिए भी ऋण सहायता दी जाती है।



सांकेतिक



DCHFC offices will open in many places for affordable housing loans

किफायती आवास ऋण के लिए कई जगह खुलेंगे डीसीएचएफसी के कार्यालय

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

दिल्ली वालों को किफायती और पारदर्शी आवास ऋण उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड (डीसीएचएफसी) का विस्तार होगा। इस कड़ी में अगले माह रोहिणी में डीसीएचएफसी का नया कार्यालय खोला जाएगा, जिससे उत्तर-पश्चिम दिल्ली समेत आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को सीधा लाभ मिले सकेगा।

इसके बाद राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में डीसीएचएफसी के नए और कार्यालय खोले जाने की योजना है। इस बाबत सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को साफ और स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

मंत्री ने बताया कि रोहिणी में खोला जाने वाला कार्यालय सीरी फोर्ट के बाद डीसीएचएफसी का दूसरा कार्यालय होगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में सहकारी क्षेत्रों की जमकर उपेक्षा की गई है, अब दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है कि मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा सहकारी आवास समितियों से जुड़े लोगों को किफायती ब्याज दरों पर आवास ऋण मिले।

साथ ही अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए जनसंपर्क मजबूत करने और प्रचार-प्रसार को प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।